supporting staff of their respective CGITs. The Ministry of Labour renders them all possible assistance to recruit the staff. It has been observed that the Local Employment Exchange or the Staff Selection Commission from which a Panel of names for the supporting staff such as Daftry, LDC, PA etc. have to be obtained, are not in a position to send the panel of names in time, as a result of which there are delays in recruitment of the supporting staff by the Presiding Officers. The Ministry also takes up the matter with the concerned authorities whenever requests are received from the Presiding Officers to render them assistance in recruiting the supporting staff.

Houses Constructed in Sainik Farm Areas

*471. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the number of houses constructed in the Sainik Farm areas in New Delhi, which is an unauthorised colony;

(b) whether Government propose to regularise it on payment of heavy penalty; and

(c) if so, the names of other unauthorised colonies which are to be regularised on the same pattern?

THE MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI RAM JETHMALANI): (a) Government of National Capital Territory of Delhi has reported that in April, 1996 there were 777 built-up structures in the Sainik Farm area.

(b) and (c) Government is already seized of the matter of regularisation of unauthorised colonies in Delhi, including Sainik Farm. The Government had set up a High Powered Committee to go into the issue of regularisation of unauthorised colonies in Delhi. The committee recommended that Sainik Farm colony should not be regularised. Different norms for regularisation of colonies will have to be adopted depending upon the status of land regarding ownership and land-use as per Delhi Master plan. The Hon'ble High Court of Delhi has restrained the Government .from regularising any unauthorised colony in Delhi till further orders. Policy on the issue of regularisation of colonies like. Sainik Farms is yet to be finalised and will be subject to the orders of the Hon'ble High Court of Delhi.

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अश्विग्रहीत की गई भूमि का उपयोग न किया जाना

*472. **श्री सुखदेव सिंह ढिंडसाः**

श्री बरजिन्दर सिंहः

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि अधिगृहीत की है किन्तु धनाभाव के कारण उसका समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी भूमि का कुल क्षेत्र कितना है जो अभी भी अनुपयुक्त है;

(ग) उस भूमि का क्षेत्रफल कितना है जिस पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है और यह कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है; और

(घ) क्या सरकार का अनुपयुक्त बेकार पड़ी भूमि को उपयोग हेतु निजी क्षेत्र को हस्तांतरिक करने का विचार है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) और (ख) जी नहीं, पैसे की कमी के कारण भूमि का उपयोग नहीं किया जा रहा, यह बात नहीं है। डी. डी. ए. ने अब तक 59,542 एकड भूमि अंधिग्रहीत की है और इस भूमि को लागू की गई विभिन्न योजनाओं और दिल्ली में नियोजित विकास के लिए लागू की गई/की जा रही योजनाओं के लिए प्रयोग किया जा रहा है। डी. डी. ए. ने सूचित किया है कि इसके द्वारा अधिग्रहीत की गई सारी भूमि का अभी उपयोग नहीं किया गया है, यह आयोजना विकास या निष्पादन के स्तर पर है।

(घ) **डी**. डी. ए. को विभिन्न परियोजनाओं के आवेदन और निष्पादन का काम चल रहा है। इन

परियोजनाओं का ब्यौरा पूरा होने की तारीख विवरण में दी गई है। (नीचे देखिए)।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं.	जगह का नाम	क्षेत्र	संभावित वर्ष जब यह काम पूरा हो जाएगा।
1	2	3	4
1.	द्वारका		
	(क) चरण-I	1862.00 है.	सन 2002 तक
	(ख) चरण-II	723.00 है.	सन् 2004 तक
2.	रोहिणी चरण-IऔरII		
	(क) सैक्टर 1 से 19	1756.00 है.	सन् 2000 तक
	(ख) चरण-III(सै. 20-25)	700.00 है	सन् 2000 तक
3.	आई.पी.एक्सटेंशन (ई-8 से ई-13) (लक्ष्मी नगर जिला केन्द्र और गीता कालोनी विस्तारित भाग)	94.00 है.	सन् 2001 तक
4.	आई एफ सी (गाजीपुर)	171.00 है	2003 तक
5.	मयूर बिहार/चिल्ला दल्लूपुरा और कोंडली घरौली	180.00 है	वही
6.	शाहदरा सी बी डी और यमुना खेल परिसर	79.00 है	2000 तक
7.	शास्त्री पार्क औऱ लोनी का पुर्वी भाग	31.00 है	2000 तक
8.	क्रांति नगर (डिस्ट्रिक्ट पार्क)	4.00 है	1998 तक
9.	वसंत कुंज	101.00 है	2003तक
10.	पश्चिमी दिल्ली अर्थात द्वारका, पश्चिम बिहार औऱ हरीनगर के इलाके	43.41 है	वहीं
11.	साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर	21.82 है	दिसंम्बर 99
12	कालकाजी	3.026 है	जून 99
13.	यूसुफ सराय	0.26 है	वही
14	तुगलकाबाद इनस्टिटयूशनल एरिया	2.58 है	मार्च 200
15.	ओखला चरण-II	7.60 है	सन् 2000 तक
16.	गीतांजलि	760.है	मार्च 99
17.	टीकरी कलई	101.00 है	सन् 2000 तक
18.	पीतमपुरा	65.74 है	सन् 2004 तक
19	जहांगीपुरी	4.19 है	सन् 1999 तक
20.	माडल टाउन	16.92 है	सन् 2002 तक
21.	भलस्वा लेंक कम्पलैक्स	92.00 हैं	सन् 1991 तक
22.	धीरपुर	156.37 है	2005 तक
23.	नरेला	598.70 है	वही
24	मोतिया खान	0.96 है	2001 तक
25.	मुखर्जी नगर	2.60 है	वही

1	2	3	4
26.	कल्याण बिहार	2.78 है	वही
27.	गोल्डन पार्क	2.41 है	2002 तक
28.	गांधी विहार	1.10 है	वही
29.	शालीमार बाग	24.10 है	वही
30.	अशोक विहार	0.295 है	2000 तक
31	गुलाबी बाग	1.15 है	वही
32.	लारेंस रोड	2.73 है	वही
33.	आई एफ सी नरेला	57.00 है	वही
	जोड़ः	6911.00 है	17070 एकड़

है. हैक्टेयर

Survey of loss making PSUs

*473. SHRI RAJNATH SINGH SURYA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether any survey of loss making PSUs been done for the years 1996-97 and 1997-98;

(b) if so, the names thereof and the extent of losses incurred by top ten PSUs during these years (sector-wise); and

(c) the steps taken to check these trends?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) and (b) Performance of Central Public Sector Enterprises is reviewed periodically. Public sector undertakings which incurred losses during the last two years *i.e.* 1995-96 and 1996-97, for which period the information is available, are given at Annexure *[See* Appendix 184, Annexure No. 89]. A Satement showing the extent of losses incurred by first 10 PSUs during 1995-96 and 1996-97, cognate group-wise also given the above Annexure.

(c) Steps taken to check the losses and improve the performance include professionalisation of Boards, periodic performance review by administrative Ministries, entering into Memorandum of Understanding with the undertakings, rationalisation of manpower, organisational and capital restructuring including formation of joint , ventures, technology upgradation, etc.

Import of used Tyres

*474. SHRI J. CHITHARANIAN: I SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the reasons for allowing import of used tyres in India;

(b) the quantity of used tyres which were imported in 1996-97 and 1997-98;

(c) how much used tyres will be imported during the year 1998-99; and

(d) the reasons for which Government are refusing to suspend or stop import of used tyres?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI RAMAKRISHNA HEGDE): (a) to (d) As per present policy the import of used tyres is permitted freely only if the per tyre c.i.f, value is US $175 and above for buses, lorries and earth moving equipment including bigger size vehicles and light commercial vehicles and US $25" and above for passenger automobile vehicles including two wheelers, three wheelers and personal type vehicles. The